and advice to the State Government to continue the development of infrastructure at Amaravati. After all, Government is a Government in succession and its existence continues whether this party comes into power or that party comes into power. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Your time is over. It will not go on record. Even if I keep quiet, it will not go on record. Shri Shwait Malik.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

**Need for commencement of work on the Amritsar Firozpur Railway link**

**श्री श्वेत मलिक** (पंजाब): चेयरमैन सर, मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूँ, जो पंजाब के लिए golden gate है और आगे पाँच स्टेट्स के साथ associate करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। यह है - Revival of Amritsar-Ferozpur Railway Link. यह partition के पहले railway link था। Partition के समय जब demarcation हुआ, तो यह railway link disturb हो गया, जिससे अमृतसर और फिरोजपुर का railway link कट गया। 20 वर्ष से यह मामला लम्बित था। कई सरकारें आईं, पर इस मामले में कोई decision नहीं हो सका। मैं प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी और पूर्व वित्त मंत्री, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 2016 में इसके लिए 299 करोड़ रुपए, almost 300 करोड़ रुपए allocate कर दिए। इसका फायदा यह है कि इस समय हमारे पास सिर्फ एक रूट है, वह है अमृतसर-ब्यास-जालंधर का railway route. उसके ऊपर congesion है, इसलिए हमें नई ट्रेन्स नहीं मिलती हैं। यह बॉर्डर स्टेट है। This will be an alternative route. अमृतसर से फिरोजपुर होते हुए यह आगे पंजाब के अन्य भागों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को connect करेगा। इससे अमृतसर से मुम्बई जाने में पाँच घंटे का रास्ता कम हो जाएगा। इससे एक तो defence को alternative route मिलेगा, क्योंकि वहाँ defence movement बहुत है, दूसरा, इस पर commercial trains चलेंगी, goods trains चलेंगी। यह मामला बहुत समय से लम्बित था। इससे विशेषकर पंजाब को हर field में और वहाँ का जो trade है, उसमें लाभ होगा। इसके साथ ही, in case of emergency also, अमृतसर को मुम्बई के साथ दो रूट्स मिल जायेंगे और अमृतसर कांडला से भी कनेक्ट हो जायेगा। 30,000 टन राइस और बहुत सा ऐसा मैटीरियल है, जो इम्पोर्ट

[श्री श्वेत मलिक]

होता है, जोकि इस रेलवे के थ्रू हो सकता है, क्योंकि लोगों को मजबूरी में ट्रक्स में भेजना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट में भेजना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट के लोगों की भी इसमें involvement रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने अब 3 साल के बाद land acquisition start किया है, but the process is very slow. So, I request an action from your end to direct the State Government कि इसको expedite किया जाए, ताकि अमृतसर को 70-72 वर्षों के बाद एक बार दोबारा रेलवे का एक नया रूट गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ मिल सके, थैंक यू।

**श्रीमती सम्पतिया उइके** (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

**श्री अमर शंकर साबले** (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

**श्री रामकुमार वर्मा** (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

**Problems face by farmers of Kashmir Valley due to heavy snowfall**

**श्री नज़ीर अहमद लवाय** (जम्मू-कश्मीर): मोहतरमुल मुक़ाम चेयरमैन साहब, मैं एक important issue, जो जम्मू-कश्मीर स्टेट से ताल्लुक रखता है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

एक महीने पहले कश्मीर घाटी में जो बर्फबारी हुई, उस बर्फबारी की वजह से वहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, फ्रूट ग्रोअर्स हैं, उनका बड़ा नुकसान हो गया। वहाँ जो पेड़ थे, वे उखड़ गये और कुछ टूट भी गये। वहाँ पर जो किसान काम करते हैं, जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, उन फ्रूट ग्रोअर्स को दवाई भी लानी पड़ती है, वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम है। कश्मीर में जो हालत पहले से ही खराब थी, उस पर नागहानी आफत की वजह से, जो unexpectedly बर्फबारी हुई, उससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ। जम्मू और कश्मीर घाटी की जो इकोनॉमी है, वह तो फ्रूट पर based है। जब फ्रूट का ही नुकसान हुआ, तो सारी घाटी में जो economic strength है, वह बिल्कुल weak हो गयी है।

मैं आपके माध्यम से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इससे कश्मीर घाटी में वहाँ के लोगों की जो हालात खराब हो गयी है, उसको assess करने के लिए एक टीम भेज दी जाए। उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, जिससे वे फ्रूट को बाहर के स्टेट्स में ले जायें। वहाँ पर जो मंडियाँ थीं, वे भी बंद पड़ी थीं। उन मंडियों में जो व्यापारी काम करते थे, उनका भी नुकसान हुआ। वे भी फ्रूट ग्रोअर्स हैं, क्योंकि कश्मीर वैली